धर्म अनुभव करने की चीज है नकल करने की नहीं।

– अज्ञात

कृषि से जुड़े तीन अहम फैसले

हमें इस हकीकत पर भी नजर डालनी होगी कि गन्ने के किसान अपनी तौली हुई फसल चीनी मिलों में पहुंचा आने और बिक्री की रसीद हासिल कर लेने के बावजूद दो–दो साल तक उसका भुगतान हासिल नहीं कर पाते।

कोमल सूद।

पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी करके कृषि से जुड़े तीन अहम फैसलों पर अमल का रास्ता साफ कर दिया। इनमें 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना और अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटाना, किसानों को अपनी फसल अधिसूचित मंडी क्षेत्र से बाहर बेचने की छूट देना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए किसानों को सीधे अपनी उपज की मार्केटिंग में उतरने की इजाजत देना शामिल है।

ये फैसले न केवल राष्ट्र हित के गंभीर मसलों से जुड़े हैं बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच कार्यक्षेत्र के विभाजन को भी छूते हैं। इसलिए सामान्य स्थितियों में अध्यादेश इसके लिए उपयुक्त रास्ता नहीं था। लेकिन आज देश की स्थितियां सामान्य नहीं हैं। कृषि क्षेत्र में और खासकर किसानों के लिए तत्काल राहत की व्यवस्था करना जरूरी है।

सरकार की दलील यही है कि इन कदमों से न केवल कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की राह खुलेगी बल्कि किसानों को लाभ के ज्यादा मौके भी मुहैया कराए जा सकेंगे। ऐसे में अध्यादेश की मजबूरी समझी जा सकती है। लेकिन याद रहे कि न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की व्यवस्था के पीछे भी दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। एक यह कि ज्यादा उत्पादन की स्थिति में किसानों को अपनी फसल कौड़ियों के मोल न बेचनी पड़े और दूसरा यह कि सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार रहे ताकि देश में 1970 के दशक से पहले की तरह बार–बार खाद्यान्न संकट की स्थिति न पैदा हो। इसमें दो राय नहीं कि इन दोनों उद्देश्यों को साधने में ये प्रावधान पूरी तरह सफल रहे। लेकिन मामले का दूसरा पहलू यह है कि संकट के उस पुराने दौर से हम काफी आगे निकल आए हैं।

बदले माहौल के मुताबिक नए प्रयोग करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। हां, इन नए प्रयोगों के दौरान हमें इनके साथ जुड़े जोखिमों पर भी लगातार नजर रखनी होगी। मसलन यह कि जिन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच हासिल नहीं है उन्हें आज भी किसान हर दूसरे–तीसरे साल सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जो कीमत उन्हें बाजार में मिल रही होती है उससे आने–जाने का भाड़ा तक नहीं निकलता।

ऐसे ही, खरीदारों के साथ किसानों के कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे किसानों का हित सुरक्षित मान लेने की दलील स्वीकार करने से पहले हमें इस हकीकत पर भी नजर डालनी होगी कि गन्ने के किसान अपनी तौली हुई फसल चीनी मिलों में पहुंचा आने और बिक्री की रसीद हासिल कर लेने के बावजूद दो–दो साल तक उसका भुगतान हासिल नहीं कर पाते। यानी एक बात साफ है कि भारत के किसानों को अभी बाजार के विवेक और सदिच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। देश के कई किसान संगठन इन बदलावों को लेकर अपनी आशंका जता चुके हैं। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी सरकार को अपनी तरफ से किसान हितों की सुरक्षा के बंदोबस्त करने ही होंगे।

अनुभव

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। भले ही आपको कितना ही बुरा अनुभव क्यों ना हुआ हो... आपको उसके भीतर छिपे अवसरों को खोजना चाहिए। ध्यान करने से आपके मस्तिष्क को स्पष्टता का अहसास होता है और यह आपके हृदय को भी विशालता देता है। आप दूसरों के प्रति संवेदना का भाव रखने लगते हैं। कभी–कभार माफ करने की भी कई परते होती हैं, जब तक आपको शांति ना मिल जाए तब तक आपको अपने भीतर झांकते रहना चाहिए। माफ करने का अर्थ हर बार यह भी नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे कानूनी रूप से भी माफी मिल जाए। अगर इस स्थिति में आपका कोई अपना, कोई बेहद करीबी शामिल है तो अपनी भावनाओं का पारस्परिक आदान–प्रदान करना आपके रिश्ते को और मजबूती दे सकता है।

संपादकीय

धर्म का अर्थ

विद्या को लेकर यही हमारी मूल सोच रही है। यहां धर्म का तातपर्य पूजा–पद्धति से कदापि नहीं है। धर्म का अर्थ समाज कल्याण है। यानी हमारे शिक्षा का अंतिम उद्देश्य समाज कल्याण होना चाहिए। इस चिंतन में तो पहले ही गिरावट है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जड़–मूल से इस चिंतन को खत्म कर देगी। अगर व्यक्ति में सहअस्तित्व, सामूहिकता एवं सहिष्णुता आदि सही ढंग से विकसित न हो पाए तो समाज भौतिक स्तर पर भले संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगितयां होंगी और जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देंगी। ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था में इन सभी सामाजिक गुणों के विकसित होने की संभावना न के बराबर है। ऊपर की बातें तो वैचारिक हो गईं, अब कुछ व्यवहारिक चीजों पर नजर डालते हैं। भारत में सामाजिक, आर्थिक विषमताएं विकराल रूप से हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरी तकनीकी साधन उपलब्ध हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनके पास कमोबेश साधन तो हैं, लेकिन घर में एकांत का अभाव है। टीवी का शोर, रसोई की आवाज, सबका उन्हें सामना करना है। ऐसे बहुत ही कम घर है जहां ऑनलाइन शिक्षा के जरूरी साधन भी हैं और माहौल भी। यह ज्ञान के मार्ग में बड़ा सामाजिक भेदभाव पैदा करेगा। हालांकि, इस तरह के भेदभाव हमारे बीच पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन इसका दायरा और बढ़ जाएगा, जोकि सामाजिक ताने–बाने के लिए बेहद घातक है। भारत जैसे देशों में ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को पार पाना अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भारत में शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा की सामाजिक भूमिका विकसित करने की दिशा में भी प्रदर्शित की गई है।

ऑनलाइन शिक्षा

शिवेंद्र कुमार

कोरोना वायरस ने मानव जीवन के साथ मानवीय मूल्यों को भी संकट में डाल दिया है। आज कोरोना ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस क्रूर वायरस ने लोगों के सामाजिक जीवन के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर डाला है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था को भी बूरी तरह प्रभावित किया है। पठन–पाठन का काम लगभग ठहर सा गया है। अगर हो भी रहा है तो वह ऑनलाइन माध्यम से। आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जूम, वेबऐक्स, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। लेकिन, बड़ा सवाल है कि क्या यह व्यवस्था कारगर है? हालांकि, कुछ ऐसी कंपनियां जो इस सिस्टम से मुनाफा कमा रही हैं इसकी जबरदस्त प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन शिक्षा देने के उद्देश्यों को हासिल करने में यह कहां तक कारगर हैं, इसकी समीक्षा बेहद जरूरी है। खासकर भारत जैसे देशों के संदर्भ में, जहां सामाजिक और आर्थिक विषमताएं चरम पर हैं। ये दोनों स्थितियां शिक्षा हासिल करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 25 करोड़ स्कूली छात्र हैं। वहीं, विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकि शिक्षा हासिल करने वाले

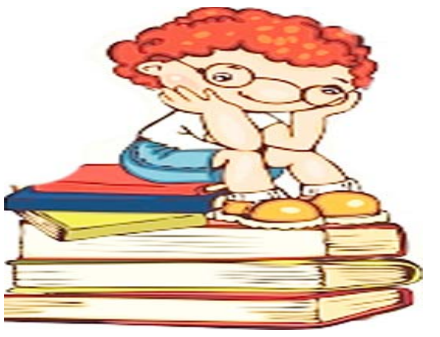

छात्रों की संख्या करीब 7 से 8 करोड़ के करीब बताई जाती है। कुल मिलाकर करीब 32 से 33 करोड़ छात्र हैं। यह आबादी अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। कोरोना ने इन 33 करोड़ छात्रों के भविष्य को बूरी तरह प्रभावित किया है। इनके शैक्षणिक ताने–बाने को लगभग तहसनहस कर दिया है। करीब ढाई महीने से ये छात्र स्कूल, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। ये घरों में कैद हैं। इनके लिए विकल्प की तलाश की गई। वह है ऑनलाइन एजुकेशन। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स और वाट्सऐप जैसे टूल की मदद से इनकी शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, बड़ा सवाल है क्या ऑनलाइन शिक्षा क्लास रूम शिक्षा का विकल्प है? यही नहीं क्या यह भारत की सामाजिक, आर्थिक परिवेश के अनुकूल है? ये तमाम सवाल आज 'यक्ष प्रश्न' बनकर छात्रों के साथ–साथ पूरे समाज के सामने खड़े हैं।

भारतीय परंपरा के मुताबिक, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के तहत व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण, छात्रों को समाज कल्याण के लिए प्रेरित करना और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास शिक्षा के मूल उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षक–छात्र के संबंध इन्हीं मूल्यों से निर्मित हुए थे। हजारों सालों से चली आ रही क्लास रूम पठन–पाठन का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान पिलाना नहीं रहा। उनके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की सतत प्रक्रिया उस शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है। क्लास रूम शिक्षा में एक साथ जीने की कला, एक–दूसरे को सहयोग करने की कला भी धीरे–धीरे विकसित होती है। सामूहिक चिंतन या यूं कहें कि सामूहिकता का भाव भी यहीं से धीरे–धीरे विकसित होता है। एक–दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी हम यहीं सीखते हैं। क्लास रूम शिक्षा व्यवस्था में गुरु–शिष्य परंपरा का अपना अलग ही आनंद है। लेकिन, ऑनलाइन शिक्षा इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में नाकाम है।

सिर्फ शिक्षा नहीं, बहुत सी शिक्षणेत्तर गतिविधियां भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए अहम होती हैं। छात्र जीवन में किए गए इन गतिविधियों का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

अपना ब्लॉग

अकेलेपन से अवसाद की तरफ ढकेल रहा

मोहन। छात्र जीवन की ये सारी गतिविधियां हमें व्यक्तित्व निर्माण की पूर्णता की तरफ ले जाती हैं। क्लास रूम और शैक्षणिक परिसर में होने वाले बहस और तर्क–वितर्क हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ऑनलाइन क्लास रूम में हम इन सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण का यह अधूरापन हमें कहां ले जाकर छोड़ेगा हमें यह पता ही नहीं। अभी छोटे से कालखंड में ही ऑनलाइन शिक्षा के दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। ऐसा देखने में आया कि बच्चों की कक्षाएं 4 से 5 घंटे तक चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों को होमवर्क भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों करीब 8 घंटा ऑनलाइन बिता रहे हैं। यह उनके मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों के लिए घातक है। इस छोटे से कालखंड में कई शिकायतें सामने आईं। ये बच्चों के भीतर आंखों की समस्याएं और उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कुछ बच्चों में मानसिक समस्याएं भी देखने को मिलीं। यह व्यवस्था उन्हें अकेलेपन से अवसाद की तरफ ढकेल सकता है।